न्यायाधीश तापसेइन *सेन के समक्ष*

डॉ. गुल्सान सतीजा , — *याचिकाकर्ता*

बनाम

नई भारत सहायता *कंपनी, — उत्तरदाता*

C.W.P. नहीं. 2000 का 15822 और
सी.एम. नहीं। 2003 का 10362

23 मार्च 2005

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — एक के खिलाफ आरोप बैंक-डेटिंग द्वारा कवर नोट जारी करने का शाखा प्रबंधक जानबूझकर, जानबूझकर, बेईमानी से और धोखे से — आरोपों को स्थापित किया गया है और अधिकारी और सजा के खिलाफ साबित हुआ है संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि का ठहराव —प्रमुख के कारण पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया उस पर लगाया गया जुर्माना — पेंडेंसी के दौरान कनिष्ठ व्यक्तियों का संवर्धन याचिकाकर्ता के खिलाफ सतर्कता का मामला — एक कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं है पदोन्नति का दावा करें लेकिन वह पदोन्नति के लिए विचार का दावा कर सकता है —याचिकाकर्ता पर लगाई गई सजा न तो कठोर है और न ही अनुपातहीन है याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के मद्देनजर — न तो आरोप-प्रत्यारोप और न ही जांच की कार्यवाही / रिपोर्ट को रद्द करने के लिए उत्तरदायी — हालांकि, सजा याचिकाकर्ता को केवल वित्तीय निहितार्थ से संबंधित है, उत्तरदाता खोलने के बाद पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार कर सकते हैं सील कवर और अगर वह अन्यथा योग्य पाया जाता है.

हेल्ड, इस आशय की रिट याचिकाकर्ता की शिकायत 1995 से 2003 तक, सील कवर न तो खोला गया है और न ही खोला गया है याचिकाकर्ता को पदोन्नति दी गई है, इस न्यायालय ने नोटिस किया है कि सही है 24 अक्टूबर, 1996 से 7 नवंबर, 2000 तक याचिकाकर्ता खुद देरी के लिए जिम्मेदार थे क्योंकि उन्होंने एक Cvil Suit दायर किया था जो आखिरकार था 7 नवंबर, 2000 को खारिज कर दिया गया और वह भी, जब उत्तरदाताओं ने इसमें एक

नागरिक संशोधन आवेदन स्थानांतरित किया गया जिसमें एक माननीय एकल न्यायाधीश ने 11 जुलाई, 2000 को एक अवलोकन के साथ इसका निपटान किया ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया प्रवास खाली हो जाएगा और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा. नतीजतन, यह मुंह में झूठ नहीं है याचिकाकर्ता राज्य और / या आरोप लगाने के लिए कि उत्तरदाता हैं मामले को निलंबित एनीमेशन की स्थिति में रखने के लिए जिम्मेदार है 1995 से 2003 तक.

आगे आयोजित, एक कर्मचारी सही के रूप में नहीं कर सकता, दावा प्रचार. वह केवल यह दावा कर सकता है कि उसके लिए विचार किया जाना चाहिए पदोन्नति. उस सीमा तक, उत्तरदाताओं की कार्रवाई होने में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया लेकिन उसके लिए प्रचार नहीं किया ऊपर दिए गए कारण के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, यह न्यायालय यह राय है कि सजा दी गई सजा न तो कठोर है और न ही इस न्यायालय को रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों को फिर से लागू करने के मार्ग पर सक्षम बनाने के लिए असंतुष्ट. हालांकि, में ले रहा है विचार करें कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा केवल वित्तीय निहितार्थ के संबंध में थी, यह आदेश नहीं होना चाहिए उत्तरदाताओं के मामले पर विचार करने के लिए एक बार माना जाता है सील कवर खोलने के बाद पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता और यदि वह अन्यथा योग्य पाया जाता है, तो उत्तरदाताओं को जरूरतमंद करना चाहिए कानून के अनुसार.

(पारस २१ और २४)

पी. एस. पटवालिया, संजीव कुमार तमाक के वरिष्ठ अधिवक्ता और वीवेक शर्मा, अधिवक्ताओं, के लिए *याचिकाकर्ता.*

अश्वानी तलवार, एडवोकेट, *प्रतिवादी के लिए.*

निर्णय

न्यायाधीश **तापसेइन सेन, जे.**

(1) समझौते के अनुसार, और जैसा कि सीखा वकील द्वारा सुझाया गया है पार्टियों के लिए, मुख्य राइट याचिका को साथ लिया गया है सिविल विविध अनुप्रयोग। उक्त सिविल विविध आवेदन, याचिकाकर्ता एक के लिए प्रार्थना करता है· उत्तरदाताओं पर दिशा के लिए याचिकाकर्ता के मामले वाले सील कवर को खोलने के लिए 1995 से प्रभाव के साथ पदोन्नति।

(2) मुख्य राइट याचिका में, याचिकाकर्ता ने चार्जेशीट (अनुलग्नक पी -1) को रद्द करने के लिए प्रार्थना की है; पूछताछ की कार्यवाही; जांच रिपोर्ट (अनुबंध) पी 6); और आदेश दिनांकित 4 वें अक्टूबर, 2000 (अनुलग्नक पी -9) जिसके द्वारा, उत्तरदाताओं ने लगाया की सजा संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धि. द याचिकाकर्ता ने मंडमस निर्देशन के एक रिट जारी करने के लिए भी प्रार्थना की है उत्तरदाताओं ने उन्हें डिवीजनल के पद पर विचार करने और बढ़ावा देने के लिए प्रबंधक और फिर वरिष्ठ प्रभागीय प्रबंधक के पद पर क्योंकि उनके लिए जूनियर व्यक्तियों को इतना पदोन्नत किया गया है. के अनुदान पर

पूर्वोक्त प्रार्थना, याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि उसे सभी दिया जाए वेतन और ब्याज के बकाया के साथ परिणामी लाभ 18% प्रति वर्ष की दर।

(3) छोटे तथ्य जो आवश्यक हैं·ध्यान दिया जाए और जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि जब वह शाखा के रूप में तैनात किया गया था जून, 1994 में चंडीगढ़ में प्रबंधक, उन्होंने शिकायत की के खिलाफ अधिकारी संघ के अध्यक्ष होने की क्षमता स्थानीय क्षेत्रीय प्रबंधक का कामकाज. प्रतिशोध में, याचिकाकर्ता मध्य सत्र, कानपुर और फिर गुड़गांव में स्थानांतरित किया गया था.

(4) ऐसा कहा जाता है कि उत्तरदाताओं ने आगे के कृत्यों का सहारा लिया याचिकाकर्ता के खिलाफ उत्पीड़न. एक चार्ज-शीट दिनांक 22 वीं नवंबर, 1994 **(अनुलग्नक P11) था** मार्च में उसकी सेवा की, 1995. उक्त चार्ज-शीट के अनुसार, उसे गलत तरीके से कहा गया था एक कवर नोट जारी किया **मिलीभगत में श्री एस.एस. नामक एक वरिष्ठ सहायक के साथ धींड्सा, उसी का समर्थन करके. दूसरा आरोप था उसी पर हस्ताक्षर करने से पहले और जिसे ढिन्दा द्वारा जारी किया गया था याचिकाकर्ता न तो प्रस्ताव प्रपत्र प्राप्त किया और न ही वाहन का निरीक्षण किया.** द **तीसरा शुल्क** एक मामले में याचिकाकर्ता था से अधिक दावे की अनुमति दी थी के रुपये से आवश्यक राशि. 2000. में इस मामले में, एक श्री अंगपाल को एक गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था बीमित व्यक्ति, श्री तेजिंदर सिंह के प्रतिनिधि. आश्चर्यजनक रूप से गवाहों की सूची में उल्लिखित गवाह श्री एस.एस. ढिन्दा, सीनियर. सहायक जो याचिकाकर्ता के साथ सह-आरोपी था और था वास्तव में 22 मार्च, 1993 को कवर नोट जारी किया. मुख्य जोर याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की बात यह थी कि जब वह काम कर रहा था सेक्टर 22 शाखा, चंडीगढ़ में शाखा प्रबंधक के रूप में, उन्होंने जानबूझकर और जानबूझकर, बेईमानी से और धोखे से काम किया बीमाकृत और श्री एस. एस. ढिन्दा और जारी किए गए कवर नोट दिनांक 23 वें मार्च, 1993 के बाद वाहन नं. HR-03 5261 एक दुर्घटना के साथ मिला था 22 मार्च, 1993 को पहले तीसरे पक्ष की चोट के दावे को जन्म दिया एम.ए.सी.टी. मुआवजे के लिए चंडीगढ़ की तारीख बनाकर 22 मार्च, 1993 को उक्त कवर नोट जारी करना और 22 मार्च, 1993 से 21 मार्च तक जोखिम अवधि दिखाना, 1994. यह प्रकट करने के इरादे से किया गया था जैसे कि के वाहन एक वैध बीमा था दुर्घटना के समय।

(5) याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरदाताओं ने निपटा दिया ढिन्दा एक अलग तरीके से और यद्यपि वह (ढिन्दा) वास्तव में तैयार था और

जारी किए गए उन्होंने कवर नोट को विवादित कर दिया, फिर भी उन्हें आरोपित किया गया

मई, 1995 में इसी अपराध के लिए. के खिलाफ एक संयुक्त जांच आयोजित की गई थी याचिकाकर्ता और ढिन्दा दोनों और केवल एक गवाह दिखाई दिया याचिकाकर्ता के खिलाफ. याचिकाकर्ता के अनुसार, एकान्त गवाह अपने बयान में, धिंदसा के अलावा और कोई नहीं था, **खुलासा किया कि विवादित कवर नोट था *किया गया* जारी किया गया द्वारा उसे याचिकाकर्ता के निर्देशों के तहत.**

(6) याचिकाकर्ता आगे एक शिकायत करता है कि ढिन्दा की याचिकाकर्ता की उपस्थिति में जांच नहीं की गई थी, भले ही वह एक अभियोग गवाह के रूप में दिखाया गया था. यह याचिकाकर्ता का मामला भी है एक विकास अधिकारी को छोड़कर किसी और की जांच नहीं की गई केवल कवर जारी करने के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति बताई गई है ध्यान दें, लेकिन याचिकाकर्ता को आरोपित करने वाला कोई बयान नहीं दिया. द याचिकाकर्ता ने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से, जांच अधिकारी ने एक हालांकि याचिकाकर्ता और ढिन्दा के संबंध में अलग-अलग जाँच रिपोर्ट दोनों अधिकारियों को दोषी पाया गया. के आधार पर ही ढिंडसा का बयान, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को पाया दोषी. याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट की आपूर्ति के बाद, वह बताया कि उन्हें ढिन्दा की जांच करने की अनुमति नहीं थी. अनुसार याचिकाकर्ता को, लगाए गए आदेश में उत्तरदाता ने स्वीकार कर लिया है याचिकाकर्ता को ढिन्दा की जिरह करने की अनुमति नहीं थी और फिर भी, दो वेतन वृद्धि के ठहराव की सजा देने के लिए आगे बढ़ा संचयी प्रभाव के साथ लेकिन ढिन्दा के मामले में, केवल एक वृद्धि बिना संचयी प्रभाव का आदेश दिया गया था. याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी सबूत के सजा दी गई और उत्तरदाताओं ने दंड के दो अलग-अलग सेटों को अपनाया, उसी अपराध के लिए, एक यांत्रिक और अवैध तरीके से काम किया है.

(7) राइट याचिका के अनुच्छेद 12 में, याचिकाकर्ता के पास है उन्होंने कहा कि उन्हें केवल 1 और 2 के आरोप में दोषी ठहराया गया था ढिन्दा के बयानों का आधार. बयानों पर विचार करने के बाद ढिन्दा द्वारा किए गए, जांच अधिकारी ने केवल अपने बयान पर भरोसा किया और उसे नहीं दिया, ढिन्दा को पार करने का कोई भी अवसर. बल्कि, याचिकाकर्ता ने किया· की सामग्री भी नहीं पता है ढिन्दा द्वारा दिए गए बयान. उन्होंने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता को केवल चार्ज नंबर 3 के संबंध में दोषी ठहराया गया है अँगपाल सिंह द्वारा दिया गया बयान जो एक गवाह के रूप में सामने आया और राज्य बना दिया. याचिकाकर्ता ने जिरह शुरू कर दी अंगपाल सिंह लेकिन जिरह पूरी होने से पहले, शेष जिरह के लिए मामला स्थगित कर दिया गया था इसके बाद अंगपाल सिंह कभी दिखाई नहीं दिए और फिर भी याचिकाकर्ता

केवल आधार पर आरोप संख्या 3 के संबंध में दोषी पाया गया है उक्त अंगपाल सिंह की. इस प्रकार, याचिकाकर्ता कहता है कि संपूर्ण जांच गलत थी और मनमानी और अवैध थी'

(() अनुच्छेद 12 में दिए गए पूर्वोक्त कथनों के उत्तर में राइट याचिका के काउंटर शपथ पत्र पर दायर किया गया उत्तरदाताओं की ओर से (इस न्यायालय में लिखित वक्तव्य के रूप में कहा जाता है), खुलासा करता है कि उन्होंने सावधानीपूर्वक दिए गए बयानों का खंडन किया है याचिकाकर्ता. उन्होंने निम्नानुसार कहा है: —

यह सुझाव देने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से पूरी तरह से गलत है

उस याचिकाकर्ता को केवल एक सह-अभियुक्त श्री एस.एस. के बयान के आधार पर आरोप संख्या 1 और 2 धींड्सा का दोषी ठहराया गया था। जैसा कि पहले ही प्रारंभिक आपत्ति में उल्लेख किया गया है नंबर 2 और लिखित के पूर्वगामी पैराग्राफ में बयान, पूछताछ से पहले पर्याप्त सबूत थे प्रभारी नंबर 1 और 2 को साबित करने के लिए अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ. पूछताछ का प्रासंगिक हिस्सा इस संदर्भ में रिपोर्ट के समय संदर्भित किया जाएगा रिट याचिका की सुनवाई. यह भी गलत है कि अब तक याचिकाकर्ता को पार करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था-जांच श्री एस.एस. ढिन्दा और जैसा कि पहले ही हो चुका है प्रारंभिक आपत्ति संख्या 2 और में उल्लेख किया गया है लिखित कथन के पूर्वगामी **पैराग्राफ याचिकाकर्ता को श्री एस.एस. धिंधा उनके रूप में गवाह और उसे पार करने का एक और अधिकार था- उसकी जांच करना. यह यह भी गलत है कि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है चार्ज नंबर 3 के**

संबंध में बयान की अनदेखी याचिकाकर्ता।श्री अंगपाल का उत्पादन करने के लिए के लिए सिंह गेज शेष के लिए जांच अधिकारी द्वारा स्थगित कर दिया गया था जिरह. हालांकि, के कारण सबसे अच्छे ज्ञात कारण याचिकाकर्ता के लिए वह कभी नहीं उत्पादन के लिए अपना अधिकार चुना श्री की अंगपाल सिंह के लिए जिरह. याचिकाकर्ता गवाहों की जिरह न करने की शिकायत नहीं कर सकते उपरोक्त प्राप्त करने में सरासर लापरवाही और कमी के कारण कहा गवाहों का उत्पादन किया. हालांकि, याचिकाकर्ता उपचार का लाभ नहीं उठाया है के वहाँ गवाह के रूप में था बयान में कुछ भी गलत नहीं है गवाहों के ऊपर। इस न्यायालय द्वारा आपूर्ति पर जोर।

(9) इस संदर्भ में, यह नहीं लेने के लिए प्रासंगिक होगा तथ्य यह है कि चार्ज-शीट प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने किया किसी भी सकारात्मक या प्रभावी उत्तर को बचाने और उस को छोड़कर फाइल न करें उन्होंने 13 मार्च, 1995 को भेजा था और जो अनुबंध में निहित है पी 3. इसके बाद की सामग्री के खराब होने पर, यह स्पष्ट है कि यह हो सकता है एक प्रभावी उत्तर के रूप में व्यवहार किए जाने के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त रूप से कहा जा सकता है. इसके विपरीत, यह खातिर एक मात्र इनकार है आरोपों से इनकार करना और इसलिए, उत्तरदाताओं की कार्रवाई एक जांच का सहारा लेने के लिए उसी से संतुष्ट नहीं हो सकता अनियमित कहा जाए. इसके अलावा, अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन में न्यायिक समीक्षा के दायरे का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय नहीं बैठता है उद्देश्यों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अपील की अदालत के रूप में साक्ष्य को फिर से तैयार करना या पुन: प्रस्तुत करना. हालांकि, संतुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता का दावा है कि जांच की कार्यवाही इससे पहले कि जांच अधिकारी खराब और अनियमित था, यह न्यायालय व्यक्तिगत रूप से पूरी जांच रिपोर्ट के माध्यम से और खुद को भ्रमित किया. उसी के माध्यम से जाने के बाद, यह स्पष्ट है कि एक विस्तृत याचिकाकर्ता को प्रासंगिक की जांच करने का अवसर दिया गया सवालों के आधार पर श्री अंगपाल सिंह सहित गवाह और जवाब और भी साक्ष्य के आधार पर एकत्र हुए, ए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई. यह आगे देखा गया है कि परीक्षा और अंगपाल सिंह के संबंध में जिरह समान रूप से विस्तृत थी 11 (ग्यारह) मूर्ख शीट्स में चल रहा है. मर्ली क्योंकि बाद में भी जिरह, इस मामले को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि जिरह के अवसर का पूर्ण खंडन नहीं कहा जा सकता है अंगपाल सिंह की क्रॉस-परीक्षा स्वयं 8 (आठ) मूर्ख में चलती है चादरें. उत्तरदाताओं द्वारा उनके काउंटर में दिया गया बयान इस हद तक हलफनामा कि कारणों के कारण सबसे अच्छा जाना जाता है याचिकाकर्ता, उन्होंने कभी भी क्रॉस-परीक्षा के लिए श्री अंगपाल सिंह के उत्पादन के लिए अपना अधिकार नहीं चुना, यह ध्यान देने योग्य है. उसको हद है, यह खुद याचिकाकर्ता है जिसे खुद को दोष देना है.

(10) इसके अलावा, फाइनल की सामग्री को पढ़ने पर अनुलग्नक पी -9 के रूप में लगाए गए आदेश और में ले रहा है चार्ज-शीट के लिए गुप्त उत्तर पर विचार करें जो द्वारा दिया गया था याचिकाकर्ता (अनुलग्नक पी -3), इस न्यायालय को कोई अनियमितता नहीं मिलती है जब महाप्रबंधक-सह-विषयक प्राधिकरण ने कहा कि "के रूप में चार्ज-शीट का कोई जवाब डॉ द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था. गुलशन सतीजा, प्रतियोगी प्राधिकरण, - वीडियो कार्यालय आदेश दिनांक 4 अक्टूबर, 1995, नियुक्त श्री एस. बालारमन, उप प्रबंधक, बैंगलोर आरओ के रूप में जांच अधिकारी.

(11) याचिकाकर्ता की ओर से बहुत कुछ तर्क दिया गया है प्रभाव जो अब तक चार्ज नंबर 1 का संबंध है, महाप्रबंधकसह-अनुशासनात्मक प्राधिकरण की सामग्री से सहमत था इस आशय के याचिकाकर्ता कि ढिन्दा के बयानों को लिया गया था किसी भी अवसर की पुष्टि के बिना जांच अधिकारी द्वारा विचार जिरह के लिए। यह सच है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण सहमत है याचिकाकर्ता के इस विवाद के साथ और इसलिए सही तरीके से त्याग दिया गया ढिन्दा के बयानों और उन्हें ध्यान में नहीं रखा. यह इस संदर्भ में है कि अनुच्छेद 2 में दिए गए कथन लिखित कथन महत्व मानता है. अनुच्छेद 2 में उत्तरदाताओं ने कहा है कि यह पूरी तरह से शामिल है कि याचिकाकर्ता केवल एस.एस. के बयान के आधार पर दोषी पाया गया था। यह भी कहा गया है कि मान लेना, लेकिन स्वीकार नहीं करना, भले ही ढिन्दा के बयानों पर ध्यान नहीं दिया गया हो, तब भी, जांच अधिकारी के सामने पर्याप्त सबूत थे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि चार्ज नं। 1 और 2 साबित हुए उसके खिलाफ. न्यायिक समीक्षा के दायरे का प्रयोग करने वाला यह न्यायालय तथ्य के निष्कर्षों को फिर से न खोलें और न ही पुन: प्रयास करने का कार्य करेंगे सबूत.

(12) सील के प्रभाव के लिए प्रस्तुतियाँ के जवाब में कवर 1995 से 2003 तक नहीं खोला गया है और याचिकाकर्ता को इन सभी वर्षों के लिए पदोन्नति नहीं दी गई है, सीखा हुआ वकील उत्तरदाताओं के लिए कहा गया है कि देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है उत्तरदाताओं लेकिन वास्तव में, यदि कोई हो, तो देरी के कारण हुआ है स्वयं लेखक का उदाहरण. इस संदर्भ में, यह होगा यह नोट करने के लिए प्रासंगिक है कि जांच रिपोर्ट 3 पर प्रस्तुत की गई थी सितंबर, 1996 (अनुलग्नक पी -6) इसके बाद, 12 सितंबर को, 1996, उत्तरदाताओं ने जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित की, — वीडियो उनके पत्र के रूप में अनुलग्नक पी -7 में निहित है कि वह उसे सूचित कर रहा था कि वह था के आधार पर प्रतिनिधित्व दर्ज करने का अवसर दिया जा रहा है जांच अधिकारी के निष्कर्ष और निष्कर्ष. उसे ए

दिया गया था 15 दिनों के भीतर अपना जवाब / प्रतिनिधित्व दर्ज करने का अवसर.

(13) उपर्युक्त पत्र / शो कारण प्राप्त करने के बाद, के याचिकाकर्ता ने खुद को लिखित याचिका के अनुच्छेद 13 में कहा है उन्होंने सूट दाखिल करके सिविल कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया. अनुलग्नक P115 सिविल जज, जूनियर द्वारा पारित 7 नवंबर, 2000 का आदेश है डिवीजन, चंडीगढ़ में लोक अदलात दिखा रहा है कि सूट (सिविल होना) 24 अक्टूबर, 1996 के सूट नंबर 365) को वास्तव में वापस ले लिया गया था

7 नवंबर, 2000 को लोक अदलात से पहले. यह भी स्पष्ट है ध्यान दें कि मुकदमा दायर करने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक राइट भी दायर किया याचिका जो इससे पहले 1996 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10673 के रूप में पंजीकृत थी अदालत जिसमें उन्होंने पदोन्नति के आदेशों को रद्द करने के लिए प्रार्थना की किन जूनियर्स को पदोन्नत किया गया और उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि एक राइट ऑफ मंडमों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदाताओं पर कमांडिंग जारी की जाती है उसे सहायक प्रबंधक के पद पर. उस स्तर पर, उत्तरदाताओं बताया कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया था पदोन्नति समिति, लेकिन एक सतर्कता मामले की पेंडेंसी के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ, उन्होंने सिफारिशें देने का फैसला किया था एक सील कवर में. 21 अगस्त, 1997 को एक डिवीजन बेंच ने बर्खास्त कर दिया राइट पेटिशन ने कहा कि कोई भी मुद्दा जारी करने के लिए कोई आधार नहीं था याचिकाकर्ता के प्रचार के संबंध में उस स्तर पर दिशा. डिवीजन बेंच ने यह भी देखा कि "विभागीय के बाद से कार्यवाही लंबित है, उत्तरदाताओं की कार्रवाई नहीं याचिकाकर्ता i4 को बढ़ावा देना बिल्कुल उचित और उचित है."

(14) यह 21 अगस्त, 1997 को अवलोकन था सिविल सूट अभी भी लंबित था. वह सूट, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है ऊपर, केवल 7 नवंबर, 2000 को खारिज कर दिया गया था.

(15) इस तथ्य पर ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि सिविल संशोधन में इस न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदाताओं को विवश किया गया था, —*वीडियो* 1999 के नागरिक संशोधन संख्या 3557 जिसमें उन्होंने चुनौती दी थी 18 मार्च, 1999 को जिला न्यायाधीश द्वारा निर्देशित आदेश ट्रायल कोर्ट ने सूट के साथ आगे बढ़ने और कंपनी को निर्देशित करने के लिए भी जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी भी अंतिम आदेश को पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना 11 जुलाई, 2000 को इस अदालत द्वारा पारित आदेश का खंडन, — वीडियो अनुलग्नक आर / 2 जो उत्तरदाताओं **द्वारा उनके काउंटर शपथ पत्र**

(लिखित बयान) में रिकॉर्ड पर लाया गया है, यह स्पष्ट है कि यह कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित आदेश को रद्द कर दिया ट्रायल कोर्ट द्वारा. उस आदेश को खाली करने के बाद, स्वतंत्रता दी गई थी यहां उत्तरदाताओं के लिए (न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदक बनाने और पहले प्रार्थना करने के लिए कहा कोर्ट कि वादी का सूट (याचिकाकर्ता) खारिज कर दिया जाए समय से पहले या प्रकृति में होने के कारण इसका खुलासा नहीं हुआ कार्रवाई का कोई कारण. सिविल रिविजनल कोर्ट जिसमें .. शामिल है न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आगे आयोजित किया उस अगर ऐसा है तो आवेदन को स्थानांतरित कर दिया गया था, उसी को मेरिट पर निपटाया जाना चाहिए.

(16) इस न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया है कि अनुमति देते समय सिविल संशोधन आवेदन, उक्त माननीय एकल न्यायाधीश ने भी देखा निम्नलिखित नुसार: -

""सबमिशन के दौरान, इसे भी लाया गया था मेरे नोटिस के कारण कि शो कारण नोटिस जारी किया गया कंपनी द्वारा, वादी-प्रतिवादी ने दायर किया था उत्तर. आगे कोई आदेश पारित नहीं किया गया था सजा देने वाला प्राधिकरण. यह भी इस न्यायालय द्वारा वांछित है कि सजा प्राधिकरण में देखा जाएगा शो कारण नोटिस का जवाब और पारित होगा नियमों के अनुसार उचित आदेश और आज से तीन महीने के भीतर नियम। "."

(17) **यह** ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त के सख्त अनुपालन में 11 जुलाई, 2000 को सिविल संशोधन में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 1999 की संख्या 3557, उत्तरदाता अधिकारियों ने पारित किया 4 अक्टूबर, 2000 को आदेश (अनुलग्नक पी / 9) जिसके द्वारा जनरल प्रबंधक-सह-अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने कहा कि शुल्क नंबर 1 था साबित हुआ और उन्होंने जांच अधिकारी के निष्कर्षों के साथ सहमति व्यक्त की चार्ज नोस 2 और 3 के संबंध में जो पाए गए थे स्थापित. उस संदर्भ में, उनकी राय थी कि प्रबंधन वर्तमान मूल को कम करने के दंड को लागू करने में उचित था अपने वर्तमान समय में स्थायी रूप से दो चरणों में याचिकाकर्ता का वेतन वेतन का पैमाना. घटनाओं के पूर्वगामी अनुक्रम के मद्देनजर, यह न्यायालय राय है कि लगाए गए आदेश में कोई अनियमितता नहीं है.

(18) श्री पटवालिया ने तब प्रस्तुत किया कि आदेश पारित किया गया था महाप्रबंधक द्वारा जो अपीलीय प्राधिकरण था और इसलिए, याचिकाकर्ता अपील करने के लिए अपनी जांघ से वंचित था. यह सच है महाप्रबंधक अपीलीय प्राधिकरण है लेकिन नियम के तहत सामान्य बीमा के 40 (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975, एक कर्मचारी को स्वतंत्रता देने का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष /

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को एक स्मारक संबोधित करें तारीख से छह महीने के भीतर वह अपीलीय की एक प्रति प्राप्त करता है प्राधिकरण. इसलिए, भले ही ऑर्डर अपीलीय द्वारा पारित किया गया था प्राधिकरण, याचिकाकर्ता अभी भी पहले एक स्मारक को प्राथमिकता दे सकता था कंपनी के अध्यक्ष / अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक.

(19) के रूप में लेखक याचिकाकर्ता की शिकायत के रूप में इनफ़ॉफ़र प्रभाव के लिए नागरिक विविध आवेदन में प्रकाश डाला गया 1995 से 2003 तक, सील कवर न तो खोला गया है और न ही खोला गया है याचिकाकर्ता को पदोन्नति दी गई, इस अदालत ने नोटिस किया कि 24 अक्टूबर, 1996 से 7 नवंबर, 2002 तक, याचिकाकर्ता स्वयं था

देरी के लिए जिम्मेदार के रूप में उन्होंने एक सिविल सूट दायर किया था जिसे अंततः 7 नवंबर, 2000 को खारिज कर दिया गया था और वह भी, जब उत्तरदाता इसमें ऊपर उल्लिखित एक नागरिक संशोधन आवेदन स्थानांतरित किया गया है एक माननीय एकल न्यायाधीश. 11 जुलाई, 2000 को उसी का निपटान किया गया एक अवलोकन के साथ कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया प्रवास होगा खाली खड़े हो जाओ और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा. नतीजतन, यह करता है याचिकाकर्ता के राज्य में झूठ नहीं बोलना और या आरोप लगाना उत्तरदाताओं ने मामले को रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया है 1995 से 2063 तक निलंबित एनीमेशन की स्थिति.

(20) उदारदाताओं के लिए सीखा वकील, के दौरान तर्कों का कोर्स, इस कोर्ट फोटो प्रतियों के लिए उत्पादित पदोन्नति समिति के विचार-विमर्श से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2001-2002 में भी पदोन्नति के लिए माना गया था लेकिन 4 अक्टूबर, 2000 को लगाए गए प्रमुख दंड के कारण वह को पदोन्नत नहीं किया गया था. इसी तरह के अभ्यास को फिर से बढ़ावा देने के लिए सहारा लिया गया था वर्ष 2003-2004 में लेकिन एक बार फिर उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया क्योंकि उसी कारण से.

(21) एक कर्मचारी, अधिकार के रूप में, पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता. वह केवल यह दावा कर सकता है कि उसे पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए. उसको हद, मामले पर विचार करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई याचिकाकर्ता ने संकेत दिए गए कारण के लिए उसे पदोन्नत नहीं किया ऊपर, के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि सजा दी गई सजा न तो कठोर है और न ही अनुपातहीन है इस न्यायालय को पुन: लागू करने के मार्ग पर चलने में सक्षम बनाने के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया सबूत.

(22) पूर्वगामी कारणों के लिए, यह अदालत मानती है कि वहाँ है इस राइट याचिका में कोई योग्यता नहीं है या तो चार्ज-शीट को रद्द करने

के लिए या पूछताछ की कार्यवाही या जाँच रिपोर्ट या आदेश दिनांकित 4 अक्टूबर, 2000.

(23) नतीजतन, राइट याचिका खारिज कर दी जाती है. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं.

(24) हालांकि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सजा याचिकाकर्ता केवल वित्तीय के संबंध में था निहितार्थ, इस आदेश को एक बार के लिए नहीं माना जाना चाहिए उत्तरदाताओं ने पदोन्नति के

लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया सील किए गए कवर को खोलना और यदि वह अन्यथा योग्य पाया जाता है, तो उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार जरूरतमंदों को करना चाहिए.

अभिस्वीकृति- *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इससे समझ सके और किसी अन्य उद्देस्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यायहारिक और आधिकारिक निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देस्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव

प्रसिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicialofficer)

नारनौल, हरियाणा